B.A.
M.A II sem.
18-20 session

Dr Kumari Manju
H.O.D. R.N.C.

Topic:
Cashless Economy

जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह खत्म हो जाये या कहें कि बराबर हो जाए तथा सभी लेन-देन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय National Electronic Funds Transfer-NEFT और RTGS (Real Time Gross Settlement) जैसे Electronic चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे तो यह स्थिति Cashless अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित की जाती है। ... देश में एक नई क्रांति आई जिसे "नकदी रहित भारत" या Cash less भारत की संज्ञा दी गई, इस क्रांति ने लोगों को नकदी में लेन-देन करने की अपनी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। इस कदम के द्वारा ... लोगों की नकदी पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति में कमी आयी है और देश में नकदी रहित लेन-देन की प्रक्रिया का विकास हो चुका है।

कैशलेस लेन-देन के प्रकार: (1) मोबाइल वॉलेट: (a) मोबाइल वॉलेट स्मार्टफोन में मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट है जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में रखे जाते हैं (b) ... पैसे को निकालना, लेन-देन तथा भुगतान अर्थात यह एक डिजिटल पर्स है जिससे पैसे को ... किया जा सकता है। (2) प्लास्टिक मनी: इसका तात्पर्य प्लास्टिक के बने कार्ड होते हैं जिसका इस्तेमाल भुगतान आदि जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड आदि के लिए किया जाता है। (3) नेट बैंकिंग: (a) किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का इंटरनेट के जरिये प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के माध्यम से करना नेट बैंकिंग कहलाता है (b) इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल एप बनाते हैं (c) तत्काल भुगतान ... अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। जैसे NEFT और RTGS नेट बैंकिंग के तहत आने वाली भुगतान प्रणालियाँ हैं। (4) Unified Payment Interface-UPI, National payment corporation of India द्वारा आरंभ की गई लेन-देन की एक प्रणाली है जो वर्चुअल payment Address-VPA का उपयोग कर धन का त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। (a) यह भुगतान का एक ऐसा माध्यम है जो पूरे सप्ताह चौबीसों घंटे काम करता है। इस सेवा का लाभ बिना किसी internet connectivity के भी उठाया जा सकता है (b) इससे धन के लेन-देन में नकदी का चलन कम हो जाएगा।

(5) Payment Bank: (a) भारतीय रिज़र्व बैंक दो प्रकार के लाइसेंस जारी करता है — सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस तथा विभेदित बैंक लाइसेंस (b) एक Payment Bank विभेदित बैंक लाइसेंस प्राप्त बैंकों की श्रेणी में आता है। payment Bank एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है। (c) इन बैंकों का उद्देश्य प्रवासी श्रमिक वर्ग-निम्न आय अर्जित करने वाले, लघु व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को सेवा प्रदान कर अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था के लाभ: (1) टैक्स की चोरी में कमी आएगी: यदि अर्थव्यवस्था Cashless होती है तो Tax की चोरी में कमी आती है क्योंकि लेन-देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं। जिससे किसी भी व्यक्ति के वास्तविक आय के संबंध में आंकड़े छुपाने में कठिनाई होती है। (2) काले धन पर रोक: (a) कैशलेस अर्थव्यवस्था का मुख्य लाभ यह भी है कि Electronic माध्यमों के जरिये आर्थिक लेन-देन होने पर ... मनी के बाजार को खत्म कर ...

(c) नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में Black Money भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली आदि जैसे आपराधिक गतिविधियों का आधार होता अनुमान बन जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था इनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करती है। (2) बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुँच: (a) यह प्रणाली सभी को बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने में अत्यंत ही सहायक होगा। (b) ऐसा इसलिए है कि इस व्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु बुनियादी ढाँचा खड़ा करने के बजाय बस एक डिजिटल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी।

(3) लागत में कमी: (a) बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी व्यक्ति विशेष पर पहुँचने की शर्त खत्म हो जाएगी, इससे लेन-देन संबन्धी शुल्क के साथ-साथ Transportation में भी कमी आएगी। (b) कैशलेस लेन-देन बढ़ने से R.B.I. द्वारा कम नोट छापने का ऑर्डर जिससे नोट छपाई पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता है। (c) इसके साथ ही ए.टी.एम. को सुचारू रूप से चालू रखने में बैंकों द्वारा होने वाला खर्च भी कम होगा। (4) जनहित में वृद्धि: जनता के कल्याणार्थ चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि पैसे बिना बिचौलिए के भेजे जाएंगे के द्वारा electronic माध्यमों से सीधे Bank Account में जायेगा।

कैशलेस अर्थव्यवस्था में कठिनाइयाँ: (1) एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे (a) देश की जनसंख्या का मात्र 50 प्रतिशत आबादी ही बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ी हुई है। जन-धन योजना लागू होने से बड़ी संख्या में Bank Account तो खुल गए लेकिन अधिकांश खातों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा है। (b) कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि इन खातों को क्रियाशील बनाया जाए।

(2) असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव: हमारे देश के अर्थव्यवस्था से एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं जो नेट बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश लेन-देन नकदी में ही किया जाता है- ऐसे में यह किसी से उम्मीद करना कि वह नकदी में प्राप्त वेतन को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करेगा।

(3) साइबर सुरक्षा का मुद्दा: आज हमारे देश में साइबर क्राइम की जोर: जोर से चल रहे हैं। अक्टूबर 2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार 30 लाख से ऊपर डेबिट कार्ड के चोरी का विवरण मिला था। इस तरह से भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस स्थिति में यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस कर दिया जाए तो हमारी सरकार को साइबर सुरक्षा में मजबूती लानी होगी।

(4) नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा इन्टरनेट की लागत: (a) ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि ग्रामीण लोगों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता या विफलता रहती है। इसके अलावा लागत के कारण ग्रामीण इससे प्रभावित हैं। (b) कार्ड पर शुल्क ऑनलाइन लेन-देन ने अतिरिक्त शुल्क होता है। डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट भारत में विक्रेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। (c) लोगों में कम्प्यूटर साक्षरता अभी भी कम है लागत भी बहुत अधिक है। (d) लोगों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन-देन करने में आशंकित रहते हैं।

रतन पी. वाटल समिति की सिफारिशें: Cashless economy में जो बाधाएं आ रही हैं उनके समाधान विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई जो रतन. पी. वाटल

Scanned with CamScanner

Page No-3

की भारतसभा में गठित हुई इस समिति की निम्न महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं : (1) एक अलग स्वतंत्र भुगतान नियामक की स्थापना,
(2) उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर प्रावधानों को शामिल करने के लिए भुगतान और निपटान अधिनियम पर पुनर्विचार
(3) R.T.G.S और NEFT 24×7 आधार पर काम करना चाहिए।
(4) डिजीटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक Fund बनाया जाना चाहिए।
(5) सभी सरकारी भुगतानों और लेन देन को डिजीटल रूप में किया जाना चाहिए, (6) शुल्कों में छूट दी जानी चाहिए, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग पर सेवा शुल्क में छूट, (7) सेवाओं का समुचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। वस्तुतः इस [सरकार अभी काम पर रही है
नीति आयोग का यह अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में स्वाईप मशीनों, कैश आदि की संख्याएँ खत्म हो जायेगी यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है।

निष्कर्ष: कैशलेस अर्थव्यवस्था के रास्ते में कठिनाई है लेकिन सरकार भीम एप, लकी ग्राहक योजना, डिजी धन योजना, जन-धन योजना आदि जैसे वित्तीय उपाय भी कर रही है। कैशलेस अर्थव्यवस्था एक ऐसा विचार है जिसको व्यावहारिक रूप में अपनाने का उचित समय आ गया है परन्तु इसके लिए हमारी सरकार को कारगार उपाय करने होंगे ताकि अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिमान और समृद्ध बनाया जा सके। एक ऐसा देश जहाँ "आज नकद और कल उधार" जैसे मुहावरे चलते हो उसके लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है। शहरों में जहाँ छोटे-छोटे व्यापारी वर्ग कैशलेस विकल्प की ओर बढ़ रहा है वहीं कस्बों और गाँवों में अभी भी लोग उत्साहित नहीं हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ विवेक बेलगामी बताते हैं कि "छोटे-छोटे काम धंधा करने वालों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले मशीन लेने की बड़े पैमाने पर जरूरत है। इनमें से ज्यादातर व्यवसायी नकद में ही लेन-देन करना चाहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था उन्नत हो तो समाज भी उन्नत होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वह देश एवं समाज ज्ञान एवं तकनीक में भी उन्नत होता है। इस उन्नति के लिए तकनीकी को और भी पुख्ता करना होगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाना भी एक तकनीक है।